

स्वागत टिप्पणी*

दुवुरी सुब्बाराव

मुझे अरविंद सुब्रमणियम, सीनियर फेलो, पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वाशिंगटन डी.सी. का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। वे शीघ्र ही हमारे समक्ष 'क्या रेन्मिनबी डालर को ढँक लेगा ?' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जो मेरी समझ में इनकी नवीनतम पुस्तक 'इक्लिप्स' पर आधारित है।

2. अरविंद का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हममें से कुछ को उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त है और यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग उनके नाम और ख्याति के बारे में जानते हैं।

महिमा और ख्याति

3. पिछले कुछ वर्षों से हम सभी ने अरविंद को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में महिमामंडित होते और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करते देखा है। उनकी कुशाग्र बुद्धि, पार्श्व चिंतन और उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल के लिए उनका व्यापक तौर पर अभिनंदन किया गया है। ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ क्योंकि संकट के शिखर पर रहने के दौरान वे संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह आवाज उठायी थी कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के पास 'स्व-बीमा' के लिए न्यूनतम आरक्षित निधियाँ होनी चाहिए। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पिछले वर्ष उनके भारत दौरे के पूर्व उन्हें ह्वाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया गया था।

इक्लिप्स

4. जबकि अरविंद की इस क्षण तक की उपलब्धि सच में प्रभावशाली रही है, उनकी हाल की पुस्तक 'इक्लिप्स : लिविंग इन द शैडो ऑफ चाइना इकोनॉमिक डौमिनेंस' ने उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर थॉट लीडर्स के शीर्षस्थ लीग में स्थान दिलाया है।

5. केवल तीन सप्ताह पहले प्रकाशित होने (16 सितंबर) से लेकर अब तक अरविंद की पुस्तक ने बौद्धिक लहरें निर्मित की हैं। इसकी समीक्षा की गयी है, समीक्षात्मक रूप से अभिनंदन किया गया है, इस पर वाद-विवाद हुआ है और बौद्धिक ख्याति वाले प्रत्येक प्रमुख प्रकाशन में वस्तुतः इसका विश्लेषण किया गया है। एक ऐसे समय में जब चीन के संबंध में प्रत्येक सप्ताह कोई न कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, तब कोई अन्य पुस्तक यदि इस प्रकार लोगों का ध्यान आकृष्ट करे और

प्रशंसा पाये तो यह सच में उल्लेखनीय होता है और यह अरविंद के गंभीर पांडित्य, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक कौशल के प्रति प्रशंसा की अभिव्यक्ति होती है। केवल विदेश नीति के विषय पर प्रकाशित की जाने वाली एक पत्रिका ने अरविंद को विश्व के शीर्षस्थ 100 विचारकों की सूची में स्थान दिया है। निस्संदेह मैं आश्चर्यचकित हूँ। यह मान्यता एक निर्णायक अभिस्वीकृति है कि वे अर्थशास्त्र की एक विधा से आगे निकल गये हैं और विश्व-स्तर पर सर्वविदित बुद्धिमान व्यक्ति बन गये हैं।

6. मैंने अरविंद की नयी किताब नहीं पढ़ी है। लेकिन तीन वर्षों से गवर्नर के पद पर रहने के कारण मैं यह जानता हूँ कि गवर्नर होने का एक अनन्य विशेषाधिकार यह होता है कि वह बिना पढ़े किसी पुस्तक के बारे में बात कर सकता है। तथापि, मैंने 'इक्लिप्स' के बारे में पढ़ा है और इसलिए मैं इस पुस्तक में अरविंद की धारणा पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

7. अरविंद की धारणा में तीन बिंदु समाविष्ट हैं :

- विश्व जीडीपी के हिस्से, व्यापार और निवेश से निर्मित एक सूचकांक द्वारा मापे जाने पर पता चलता है कि लोग जितना सोचते हैं उससे पहले ही चीन विश्व की प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन की हिस्सेदारी 1970 के दशक के अमेरिका की हिस्सेदारी के बराबर और एक सदी पहले के ब्रिटेन की हिस्सेदारी के बराबर हो जायेगी।
- चीन के शीर्ष स्थान पर पहुँचने की दौड़ में जो तीन बल काम करेंगे, वे हैं (क) जनसांख्यिकी, (ख) अभिसरण, जो 'पकड़' का क्षेत्र होता है और (ग) गुरुत्व, जो किसी देश की व्यापार संभावना का माप होता है।
- विश्व को चीन के उत्थान से सामंजस्य रखने के लिए नीतियों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में निरंतर खुलेपन के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए।

8. अरविंद के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विवादास्पद हैं और इन पर विवाद हो सकता है। तथापि, बौद्धिक अखंडता की सर्वोत्तम प्रथा में:

- वे अमेरिकी और चीनी वृद्धि दरों के बारे में अपनी मान्यता को स्पष्ट रूप से अधिकथित करते हैं।

*7 अक्टूबर 2011 को आरबीआई ऑटोरियम, मुम्बई में डॉ.अरविंद सुब्रमणियम द्वारा प्रस्तुत किया गया भाषण 'क्या रेन्मिनबी डॉलर को ढँक लेगा ?' के अवसर पर डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी स्वागत टिप्पणी।

- ii. मेरा मानना है कि चीन की वृद्धि दर पर वे वस्तुतः संतुलित अनुमान लगाते हैं जो पिछले दो दशकों में इसके उत्कृष्ट कार्यसंपादन से संगति रखता है।
- iii. वे स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उन्नीसवीं सदी में जिस गति से अमेरिका कैसे ब्रिटेन से आगे निकल गया था उससे तेज गति से चीन इक्कीसवीं सदी में अमेरिका से आगे निकल जायेगा।

अरविंद के तर्क

9. अरविंद के तर्क और निष्कर्ष अनेक कारणों से विश्वासोत्पादक होते हैं।

- i. चीन ने पिछले दो दशकों में चकाचक वृद्धि-निष्पादन किया है। हम सूक्ष्म अंकों पर विवाद कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने लाखों-करोड़ों गरीब लोगों की गरीबी दूर कर उन्हें ऊपर उठाने का जो काम किया है वह मानव इतिहास में सर्वाधिक शानदार उपलब्धि रही है।
- ii. पिछले वर्ष चीन ने दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माता के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था और वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया।
- iii. चीन के वृद्धि मॉडल और काम करने का चीनी तरीका लोगों को अनिच्छा से उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य करता है भले ही वह तर्कसंगति रखे।

प्रश्न

10. इसके साथ-साथ, ऐसे अनेक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या चीन अपने कार्य-निष्पादन की गति बनाये रख सकता है और शीर्ष स्थान पर आ सकता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सूचीबद्ध करता हूँ।

- i. क्या चीन का वृद्धि इंजन अपनी गति बनाये रख सकता है ? क्या निर्यात पर जोर देने वाला तथाकथित 'चीनी मॉडल' इन्वेस्टमेंट बिज और दमित घरेलू उपभोग धारणीय है, विशेष रूप से एक बड़े बहुजातीय देश में जिसकी आबादी 1.5 बिलियन से अधिक हो ? विशेष रूप से,
 - (क) क्या बाह्य वातावरण निर्यात की गति को बनाये रखेगा ?
 - (ख) क्या कोई देश वर्ष-दर-वर्ष अपने जीडीपी के 50 प्रतिशत का निवेश करना अत्यधिक क्षमता हासमान

समान प्रतिफल और भिन्नकालिक अनर्जक ऋण समस्या को आहत किये बिना जारी रख सकता है? संक्षेप में कहें तो क्या चीन की गति अवरुद्ध नहीं हो जायेगी ?

- ii. दूसरा, क्या चीन व्यवस्थित और नपे-तुले तरीके से बाह्य और घरेलू माँग में और निवेश से उपभोग में रणनीतिक समायोजन कर सकता है जिसे लोग 'पुनर्संतुलन' कहते हैं ?
- iii. प्रश्नों के दूसरे सेट का संबंध इससे है कि तब क्या होगा जब चीन 'कैच अप' वृद्धि के लिए गुंजाइश समाप्त कर दे, जैसाकि पहले से ही दिखाई दे रहा है। क्या यह बुढ़ाती आबादी और बढ़ती वास्तविक मजदूरी के कारण 'मिडल इन्कम ट्रैप' में नहीं फँसेगा ? क्या चीन वृद्धि के नये स्रोतों का अन्वेषण करने में समर्थ होगा ताकि यह 'मिडल इन्कम ट्रैप' से बचने के लिए मूल्य शृंखला को गति देता रहे ?
- iv. चौथा, एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या चीन सत्तावादी प्रणाली के रहने पर भी अपना प्रभुत्व कायम रख सकेगा ? निस्संदेह, अब तक की चीन की सफलता ने चीन के सत्तावादी मॉडल को लगभग तर्कसंगति प्रदान की है। क्या निरंतर सत्तावाद का रहना चीन के शीर्ष तक बढ़ने के लिए प्लस-पाइंट होगा या यह एक अवरोध होगा ? क्या यह प्रणाली अपने ही भार के कारण विस्फोटित हो जायेगी या जैसाकि कुछ विश्लेषक तर्क देते हैं, क्या चीन की बढ़ती समृद्धि स्वयं सत्तावाद को समेटने के लिए अवसर प्रदान करेगी और प्रजातंत्र की ओर प्रस्थान करने की रूपरेखा तैयार करेगी ?
- v. अंत में, यहाँ एक अधिक प्रासंगिक प्रश्न रिजर्व बैंक में यह है कि 'रेन्मिनबी का क्या होगा, विशेष रूप से इसकी संभावित अंतरराष्ट्रीय हैसियत क्या होगी ?' नजर में आने वाली किसी भी मुद्रा से अलग हम भारत में यह विचार रखते हैं कि किसी भी मुद्रा के वैश्विक रिजर्व मुद्रा बनने के लिए इसमें कतिपय गुण होने चाहिए :
 - (क) मुद्रा को मुक्त रूप से चालू और पूँजीगत लेखा के संबंध में परिवर्तनीय होना चाहिए;
 - (ख) इसकी विनिमय दर आपूर्ति और माँग के बाजार बल द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए;
 - (ग) विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपेक्षित रिजर्व मुद्रा में इनवाइस किया जाना चाहिए;

- (घ) रिजर्व मुद्रा जारी करने के अनियंत्रित विशेषाधिकार का उपभोग करने के लिए जारीकर्ता देश को मुद्रा में पर्याप्त नकदी बनाये रखने की विशिष्ट जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए;
- (ङ) इसके वित्तीय बाजारों को खुला, सघन और सुदृढ़ होना चाहिए;
- (ढ) देश की नीतियाँ लोगों में विश्वास और भरोसा जगाती हों।

चीन और भारत

11. मेरा मानना है कि मैंने अनेक प्रश्न उठाये हैं। लेकिन मैं भारत और चीन की तुलना के संबंध में कुछ विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ जो लगभग राष्ट्रीय आवेश बन गयी है।
12. भारत में हमारे लिए चीन का अर्थ अनेक संदर्भों में है - ईर्ष्या की वस्तु, एक चुनौती और एक प्रेरणा।
13. यह नोट किया जाये कि वर्ष 1700 में भारत 165 मिलियन आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जिसके बाद 138 मिलियन लोगों के साथ चीन का स्थान था। एक सदी के बाद भी वर्ष 1820 में जब औद्योगिक क्रांति जोर पकड़ रही थी, भारत और चीन आधी दुनिया के जीडीपी के लिए जिम्मेवार थे। उसके बाद सामाजिक पदानुक्रम पूरी तरह बदल गया। भारत और चीन राष्ट्र संघ के सबसे

निचले पायदान पर खिसक गये। और पिछले 25 वर्षों से हम पहले की तरह बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

14. लेकिन चीन हमसे मीलों आगे है। चीन पहले से ही मध्यम आय वाला देश है जबकि भारत अभी भी न्यून आय वाला देश है और दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोगों का घर है। हाल ही में वर्ष 1990 तक भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में चीन से 30 पायदान आगे था। अब हम चीन से 30 पायदान पीछे हैं। हाल ही में, वर्ष 2000 तक शीर्ष वैश्विक संस्थाओं में कम से कम एक भारतीय विश्वविद्यालय /संस्था का स्थान होता था जबकि चीन का कोई स्थान नहीं था। आज चीन के पाँच हैं और भारत का एक भी नहीं है। पंजीकृत कराये गये पेटेंटों या शोध प्रकाशनों द्वारा मापे जाने पर चीन आगे की ओर बढ़ रहा है और भारत पीछे की ओर जा रहा है।

15. मैं यह तुलना निराशा में नहीं कर रहा हूँ बल्कि आत्म-निरीक्षण कर रहा हूँ कि भारत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यह उस गौरव को प्राप्त कर सके जिसे उसने श्रेष्ठ विश्व-शक्ति के रूप में 300 वर्ष पहले देखा था। इस हद तक चीन ने यह दिखाया है कि क्या कुछ संभव हो सकता है। इस हद तक चीन प्रेरणा-स्रोत है। भारत में हमारा यह कार्य होगा कि हम उस रिकार्ड को छू सकें या उससे आगे निकल जायें, लेकिन ऐसा हम भारतीय तरीके से करेंगे।

16. मुझे विश्वास है कि चीन के शीर्ष स्थान तक बढ़ने के बारे में अरविंद से कुछ सुनना इनमें से अनेक प्रश्नों का उत्तर देगा और हमें हमारे भावी पथ के लिए भी राह सुझायेगा।

17. कृपया आप भी मेरे साथ अरविंद का स्वागत करें।